



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय - 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैंक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक : 31 मार्च 2020

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अभावपि ने तालाबंदी के दौरान उत्पन्न हुई शैक्षणिक समस्याओं को लेकर MHRD को सौंपा ज्ञापन मध्याह्न भोजन का राशन छात्रों के घर पहुंचाने की मांग

COVID-19 के खिलाफ चल रही इस निर्णायक लड़ाई के लिए भारत में 21 दिनों की तालाबंदी का प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ रहा है। जिसे देखते हुए अभावपि ने देशभर के शिक्षा जगत से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान की ओर बढ़ने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को आज ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र समस्याओं के निवारण की मांग की है।

अभावपि ने ज्ञापन के माध्यम से छात्रों के लिए ऑनलाइन माध्यमों से पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्थिति सामान्य होने तक के लिए सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं तथा विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित करने, आवास, आवागमन तथा भोजन की समस्या से जूझ रहे छात्रों के लिए हेलपलाइन नंबर जारी कर सहायता करने, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति आदि के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति तथा शोधवृत्ति शीघ्र प्रदान करने, छात्रों के घरों तक मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) पहुंचाने की व्यवस्था करने, कोरोना वायरस महामारी के समाप्त होने के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु अभी से प्राध्यापकों की समिति का गठन करने तथा गरीब, वंचित एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों का आगामी सत्र का शुल्क माफ करने आदि विषयों की चर्चा की है।

अभावपि की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "इस समय पूरा देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है, छात्रों के सामने भी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। उनकी शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमने सरकार से मांग की है, कि सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने तक के लिए स्थगित किया जाए तथा स्थिति सामान्य होने पर ही ये गतिविधियां प्रारम्भ हों। मिड-डे मील की व्यवस्था, भोजन या खाद्य सामग्री छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग हमने की है। हम आशा करते हैं, कि छात्रों के हित में सरकार तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशासन महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)